हिंदी भाषी राज्यों पर पकड़ करने की रणनीति 850 लोकसभा सीटें !

वीरेंद्र वर्मा

इंदौर. देश में जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है. एक अनुमान के अनुसार देश की संसद में 850 लोकसभा सीटें करने की तैयारी की जा रही है. वर्तमान 543 लोकसभा सीटें और करीब 50 साल से परिसीमन नहीं होना बताया जा रहा है. इसमें मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा, बल्कि चुनाव आयोग ही सर्वेसर्वा होगा. यह बात जरूर है कि परिसीमन आयोग का गठन में एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, चुनाव आयोग का एक सदस्य मुखिया होंगे.

देश की वर्तमान सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर करने की तैयारी में जुटी है. इसका मतलब यह है कि देश में अब 543 सदस्यों वाली नहीं ,बल्कि 850 सदस्यों वाली संसद होगी. इतना ही नहीं कई राज्यों में विधानसभा की सीटें काफी मात्रा में बढ़ जाएगी. उस स्थिति में उच्च सदन राज्यसभा में भी सीटों के संख्या दो गुनी हो जाएगी. अभी राज्यसभा में 250 सीटें और 245 राज्यसभा सदस्य हैं. इसमें से कुछ सदस्यों को सरकार द्वारा सदन में नामित किया जाता है, हालांकि उनकी संख्या 5 से 8 तक सीमित रहती है. कहा जा सकता है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन में राज्यसभा की सीटें भी 400 के आसपास हो जाएगी. नव भारत ने नवंबर में बता दिया था कि

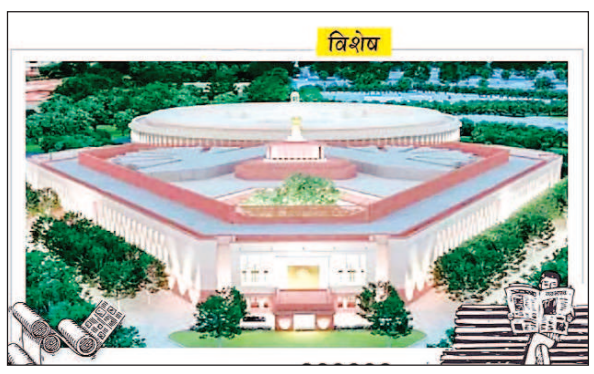

देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी. उसके अनुसार मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 की जगह 49 सीटें और विधानसभा में 230 के स्थान पर 320 से 350 सीटें हो सकती है. साथ ही इंदौर में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 9 सीटों के स्थान पर 12 से 14 सीटें करने प्रस्ताव हो चुका है. आगे परिसीमन कब से शुरू होगा? यह अलग बात है, लेकिन परिसीमन आयोग में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को मुखिया बनाकर जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है. **दक्षिण से विरोध शुरू**- परिसीमन द्वारा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में 850 सीटें करने के संशोधन विधेयक पारित करने का विरोध भी हो गया है. दक्षिण ने भाजपा की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है. तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने विरोध में कहा कि परिसीमन से दक्षिण को नुकसान और उत्तर भारत को फायदा पहुंचा तो चुप नहीं बैठेंगे. दूसरी ओर परिसीमन को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, सिद्धारमैया, पिनराई विजयन और एन रंगास्वामी ने उक्त मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की है, जिससे दक्षिण के संभावित सीटों के नुकसान की लड़ाई लड़ी जा सके. **परिसीमन जनगणना के आधार पर** -भाजपा दक्षिण को एक तरफ करके हिंदी भाषी राज्यों पर एक तरफा कब्जा करने की रणनीति से काम कर रही है. इसको इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ,राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, उतराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हिंदी या हिंदुत्व विचारधारा के अधिकतम राज्यों में से है. उक्त राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शुद्ध हिंदी भाषी राज्यों के साथ हिंदुत्व के स्थाई गढ़ भी माने जाते हैं.

इस तरह बढ़ सकती हैं सीटें

दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना मिलाकर करीब 130 लोकसभा सीटें है. यहां दो गुना सीटें भी बढ़ी तो दक्षिण भारत देश के अन्य राज्यों से बहुमत आंकड़े में पिछड़ जाएगा. दक्षिण में टोटल 250 लोकसभा की सीटें होने की संभावना है. ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश करीब 80 से 200, बिहार और झारखंड मिलाकर 53 सीटों से 85-90, महाराष्ट्र 48 से 75, मध्य प्रदेश 29 से 48-49, राजस्थान 25 से 40, गुजरात में 25 से 40 छत्तीसगढ़ 10 से 16 और, हरियाणा 11 से 18 और उतराखंड 5 से 10 लोकसभा सीटें जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. वर्तमान में उपरोक्त राज्यों में करीब 287 सीटें है और लगभग 252 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस तरह से कुल 539 लोकसभा सीटें हो जाती है.

सरकार में बने रहने पर नहीं होगी समस्या-प्रस्तावित उपरोक्त 539 सीटों में से 80 प्रतिशत 431 सीटें वर्तमान सरकार और पार्टी को सपोर्ट करती है. प्रस्तावित 850 में से 420 सीटें बचती है, जिसमें दक्षिण की 250 पर एक भी सीट नहीं जीतने पर भी सरकार में बने रहने में कोई समस्या नहीं होगी और एनडीए के सहयोगी दल साथ होंगे. इसमें अभी बंगाल, असम, उड़ीसा और छोटे राज्य मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम सहित छोटे राज्यों में एक या दो सीट के आने या नहीं आने से सत्तारूढ़ पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है.

नए फोरलेन की सीएम पैदल चलकर परखेंगे गुणवत्ता

- एडवोकेट मेहता के नाम पर होगा फोरलेन का नामकरण
- 18 करोड़ से तैयार वीआईपी सड़क

नवभारत न्यूज

उज्जैन. महाकाल की नगरी उज्जैन में विकास की रफ्तार अब सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ और तेज़ होती नजर आ रही है. इसी क्रम में शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. कोठी रोड से देवास रोड को जोड़ने वाला आधुनिक फोरलेन मार्ग बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण 19 अप्रैल को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. खास बात यह रहेगी कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मार्ग पर पैदल चलकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, जिससे इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से परखा जा सके.

करीब 800 मीटर लंबे इस मार्ग को अत्याधुनिक स्वरूप देते हुए एमआर-10 से जोड़कर विक्रम नगर तक विस्तारित किया गया है. इससे शहर के प्रमुख प्रशासनिक, शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा. लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह सड़क आने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालुओं और वीआईपी मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी.

वीआईपी कॉरिडोर के रूप में किया विकसित-यह मार्ग कलेक्टर- कमिश्नर कार्यालय, जिला न्यायालय, विक्रम विश्वविद्यालय और देवास रोड जैसे अहम स्थानों को जोड़ता है, जिससे इसे वीआईपी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है. मार्ग के आसपास स्मार्ट सिटी के तहत संस्कृत

विभाग और वीर भारत न्यास के संयुक्त प्रकल्प के रूप में एक संग्रहालय भी आकार ले रहा है, जिसमें उज्जैन के गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा.

प्रशासनिक संकुल के सामने मंच-लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल के सामने मुख्य मंच तैयार किया जा रहा है, जहां से विकास और सिंहस्थ 2028 की रूपरेखा को लेकर संबोधन होगा. पूरे मार्ग को आकर्षक लाइटिंग, रंग-रोगन, हरियाली और सजावटी पौधों से संवारा जा रहा है, ताकि यह मार्ग शहर की नई पहचान बन सके.

5017 करोड़ की योजना

5017 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना का उद्देश्य उज्जैन से जावरा तक यात्रा को आसान बनाना है. ये प्रोजेक्ट इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे उज्जैन, नागदा, खाचरौद और रतलाम जिलों के विकास को गति मिलेगी. यह एक नॉन-एलिवेटेड (जमीन स्तर पर) एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन होगा,जिसका 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है. इस परियोजना से माल ढुलाई में तेजी आएगी और किसानों व व्यापारियों के लिए राजस्थान-दिल्ली-मुंबई तक पहुंच आसान होगी.

मेहता के नाम पर सड़क का नामकरण

इस सड़क का नामकरण भी विशेष महत्व रखता है. नगर निगम की मेयर इन काउंसिल में पारित प्रस्ताव के अनुसार इस मार्ग को प्रख्यात विधिवेत्ता स्व. प्रताप मेहता के नाम से समर्पित किया जाएगा, जिससे शहर के विधिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान मिलेगा.

गूंजेगी शहनाई, मुख्यमंत्री होंगे शामिल

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 19 अप्रैल को उज्जैन आएंगे तो सामूहिक विवाह में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह और निकाह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है कार्तिक मेला मैदान पर 100 जोड़ों का विवाह होगा, साथ ही सोमवारीया कम्युनिटी हाल में 12 जोड़ों का निकाह होगा। साथ ही भाजपा नगर कोषाध्यक्ष प्रकाश यादव के निवास हामुखेड़ी पर भी सामूहिक जोड़ों का विवाह समारोह रखा गया है ,यहां पर भजन संध्या और मंदिर का लोकार्पण भी है, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव यहां भी शामिल होंगे।

ग्रीनफील्ड फोरलेन का भूमि पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 19 अप्रैल को उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का भूमि पूजन भी उज्जैन से वर्चुअल किया जाएगा. यह रतलाम और उज्जैन क्षेत्र के लिए एक बड़ी विकास परियोजना है.

आदि शंकराचार्य का दर्शन भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिक एकता का आधार

मुख्यमंत्री ने किया एकात्म पर्व का शुभारंभ

नवभारत न्यूज़

खंडवा/ओंकारेश्वर. ओंकारेश्वर में आयोजित पांच दिवसीय आदि शंकराचार्य प्रकटोत्सव 'एकात्म पर्व' का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया. उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक एकता का मूल आधार है तथा ओंकारेश्वर एकात्मता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने अद्वैत लोक एवं अक्षर ब्रह्म प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वैदिक अनुष्ठान में भाग लिया. इस अवसर पर स्वामी सदानंद

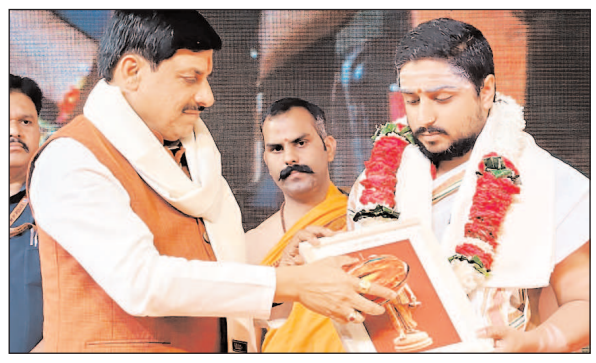

सरस्वती, पद्मश्री निवेदिता भिड़े सहित संत एवं विद्वान उपस्थित रहे. कार्यक्रम का आयोजन राज्य संस्कृति विभाग एवं आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा 17 से 21 अप्रैल तक किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने 'वेदांत सिद्धांत चंद्रिका-विद उद्गार' पुस्तक का विमोचन तथा एकात्म धाम की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया.

700 से अधिक युवा संकल्प लेंगे

कार्यक्रम में बताया गया कि 21 अप्रैल को दीक्षा समारोह में 700 से अधिक युवा 'शंकर दूत' के रूप में संकल्प लेंगे. साथ ही जनवरी 2027 से आचार्य शंकर के जन्मस्थान से एकात्म यात्रा प्रारंभ की जाएगी. ओंकारेश्वर में विकसित हो रहे एकात्म धाम और अद्वैत लोक संग्रहालय के माध्यम से इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

10 वीं में पूरक आने पर छात्रा ने कुएं में कूदकर दी जान

शहडोल. मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरई में दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने परीक्षा में दो विषयों में पूरक आने पर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका की पहचान टिंकल सिंह कंवर के रूप में हुई है.

परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद वह मानसिक रूप से व्यथित थी. आज सुबह उसका शव कुएं में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है.

केंद्र की मंशा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

आरक्षण कानून : स्पष्टता-निरंतरता के अभाव का लगाया आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल,17 अप्रैल. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को महिलाओं के आरक्षण कानून के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसके रुख में स्पष्टता और निरंतरता के अभाव का आरोप लगाया.

राजधानी भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर सरकार की स्थिति पर प्रश्नचिह्न

लगाया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में पारित इस कानून में स्पष्ट प्रावधान था कि इसके क्रियान्वयन से पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. नायक ने आरोप लगाया कि हालिया घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि केंद्र सरकार अपने ही प्रावधानों से पीछे हटती नजर आ रही है, जिससे देशभर में भ्रम की स्थिति बन रही है.

अभय दुबे ने भी जताई आपत्ति

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पूर्व में अधिसूचना जारी होने के बावजूद इसी विषय से जुड़े संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर उस पर चर्चा और मतदान का औचित्य क्या है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पैनलिस्ट अभय दुबे ने भी बिना पूर्ण कानूनी अधिसूचना के संशोधन लाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए केंद्र पर जातिगत जनगणना से बचने का आरोप लगाया.

साक्ष्य सुदृढ़ करने कार्यशाला आयोजित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 अप्रैल. पुलिस मुख्यालय स्थित राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा 15 एवं 16 अप्रैल 2026 को दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य जिला एवं विशेष पुलिस इकाइयों में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम प्रणाली और मापन संग्रहण इकाइयों के प्रभावी संचालन को सुदृढ़ करना था.

कार्यशाला का आयोजन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, जयदीप प्रसाद के निर्देशन में किया गया. इसका मुख्य फोकस आधुनिक तकनीकों के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य के संग्रहण और

प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना रहा. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से आए विशेषज्ञों ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम सिस्टम और मापन संग्रहण इकाइयाँ के संचालन पर विस्तृत सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया. प्रतिभागियों को उन्नत तकनीकों के उपयोग, डेटा संग्रहण की शुद्धता तथा डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षित किया गया.

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के तहत पुलिस एवं जांच एजेंसियों को आरोपियों, गिरफ्तार व्यक्तियों या दोषियों के फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक डेटा सहित विभिन्न माप एकत्र, सुरक्षित और विश्लेषित करने का अधिकार प्राप्त है.

खुले चेंबर में गिरने से मजदूर की मौत

ग्वालियर. शहर में सीवर चेंबर एक युवक की मौत का कारण बन गया. खुले पड़े सीवर चेंबर में गिरने से युवक की मौत हो गई. घटना गणेश कॉलोनी ओफो की बगिया की है. शुक्रवार की शाम स्थानीय लोगों ने युवक को चेंबर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक अपनी मां से खाना बनाने की कहकर निकला था और उसके बाद वापस नहीं लौटा. हादसे का पता चलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गणेश कालोनी में रहने वाले सौरभ बाथम की सीवर के चेंबर में गिरने से मौत हो गई. सौरभ के बारे में बताया गया है कि वह मजदूरी करता था और शराब पीने का आदी था.

पेज एक का शेष

महिला आरक्षण बिल गिरा

बिल पर 56 महिला सांसदों और 130 सदस्यों ने अपनी बात रखी. 127 सीटों पर 20 लाख से ज्यादा आबादी है. 1972 में परिसीमन 525 से बढ़ाकर 585 हुई थी. महिला आरक्षण देना है तो परिसीमन जरूरी है. कांग्रेस ने गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है. विपक्ष भ्रांतियां फैलाना चाहती है. पांच राज्यों में 129 से बढ़कर 195 सीटें होंगी. आरक्षण में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है. 51 और 71 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था. कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया और आज तक संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है. कांग्रेस ने कभी ओबीसी से मंत्री नहीं बनाया. भाजपा ने ओबीसी से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर इतिहास रचा. मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से है. विपक्ष ने महिला आरक्षण का भी विरोध किया. जबकि हमने 52 करोड़ महिलाओं को स्टार्टअप से जोड़ा है. 5 लाख करोड़ का बजट महिलाओं के लिए लाया गया. बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस के भागने का मौका भी नहीं मिलेगा. विपक्ष ने मोदी के हर काम का विरोध किया, जबकि हर घर हर नल से महिलाओं को फायदा हुआ. शाह ने कहा- मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था. आपकी जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा बनी रही. वे कहते हैं कायर हैं, सरेंडर कर रहे हैं. असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है. संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं.

भोपाल में प्रदर्शन की घोषणा

संविदा श्रमिकों ने वेतन उल्लंघन का लगाया आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल,17 अप्रैल. वैधानिक न्यूनतम वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश के हजारों अस्थायी, आउटसोर्स एवं संविदा श्रमिकों ने 28 अप्रैल को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की है. श्रमिकों का कहना है कि

सरकार द्वारा मासिक न्यूनतम वेतन 12,425 से 16,769 रुपये तय होने के बावजूद कई विभागों और औद्योगिक इकाइयों में उन्हें मात्र 3,000 से 5,000 रुपये तक ही भुगतान किया जा रहा है.

प्रादेशिक सेना में शामिल हों एक अधिकारी के रूप में

www.indianarmy.nic.in

कार्यरत युवा पुरुषों और महिलाओं से प्रादेशिक सेना अधिकारी (गैर-विभागीय) के रूप में राष्ट्र की सेवा करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

कुल रिक्तियों की संख्या

(ए) पुरुष - 11 (बी) महिला - 01

नोट: संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों में परिवर्तन हो सकता है।

पात्रता शर्तें

- राष्ट्रीयता: केवल भारत के नागरिक (पुरुष और महिला)।
- आयु सीमा: आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 18 से 42 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
- शारीरिक मानक: उम्मीदवार शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से सभी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए।
- रोजगार: लाभकारी रूप से कार्यरत।
- ऑनलाइन परीक्षा की तिथि: 12 जुलाई 2026।
  नोट: उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा तिथि सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार परिवर्तित की जा सकती है।
- आवेदन कैसे करें: उम्मीदवारों को वेबसाइट www.indianarmy.nic.in का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य माध्यम की अनुमति नहीं है।
- आवेदन जमा करना: ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन 20 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।
- शुल्क विवरण: उम्मीदवारों को रू. 500/- (केवल पांच सौ मात्र) का शुल्क देना होगा।

नोट:

1. प्रादेशिक सेना में भर्ती/नियुक्ति पूरी तरह से पारदर्शी और निःशुल्क है। दलालों से सावधान रहें।
2. विस्तृत अधिसूचना के लिए कृपया www.indianarmy.nic.in पर नियमित रूप से जाएँ।

CBC 10120/11/0002/2627

समाज के हर वर्ग तक संवाद और संपर्क बनाना जरुरी

भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. यादव ने कहा

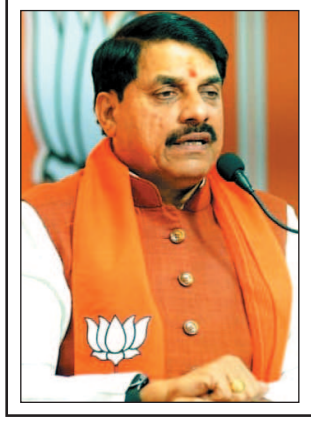

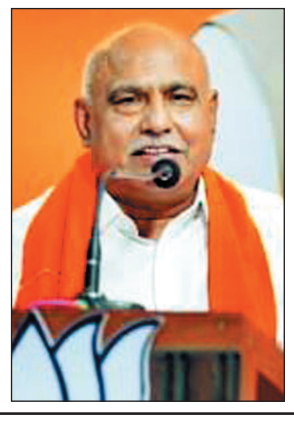

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संभाग और जिला प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया.

बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग-2026 पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकजुटता अनिवार्य है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार के विकासोन्मुखी योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ जुटना है. जब तक हम सब मिलकर पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी योजनाओं में सफलता नहीं मिल सकती. पार्टी की सफलता केवल चुनावी जीत में नहीं, बल्कि समाज में भाजपा की स्थायी पहचान और सेवा की भावना से भी जुड़ी हुई है.

> हमारी सरकार और संगठन की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि भाजपा की नीतियों और योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके. भाजपा की जीत केवल चुनावी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाज में पार्टी की स्थायी पहचान और सेवा की भावना से जुड़ी हुई है. पार्टी की सफलता का आधार सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी सेवा और भाजपा की स्थायी पहचान भी है. हमें सिर्फ चुनावी सफलता ही नहीं, बल्कि समाज में स्थायित्व और विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60